राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, सोमवार , 08 जून 2026
वर्ष 14,अंक 59, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

बच्चों के भविष्य और गांव के माहौल को बचाने के लिए आगे आए कुढ़ा गांव के ग्रामीण...03

कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर की बढ़ीं मुश्किलें, 8 जून को दाखिल करेंगे जमानत याचिका...04

पटना फायरिंग मामला: सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे थे खान सर, लेकिन आज का टाइम हुआ पूरा

● बिहार के मशहूर शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा और कथित फायरिंग मामले में सरेंडर करने पहुंचे. उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है

बिहार के मशहूर शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक खान सर आज शनिवार को पटना की अदालत में सरेंडर करने पहुंचे. कोर्ट का आज का समय पूरा होने के कराण अब वह सोमवार को अग्रिम जमानत की कोशिश करेंगे. खान सर के खिलाफ कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा और फायरिंग मामले में स्नढ्ढक्र दर्ज हुई है. आर्म्स एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है.पुलिस उनकी तलाश कर रही थी. आरोप है कि उन्होंने बॉडीगार्ड्स से कह कर फायरिंग करवाई थी।

इस मामले में पुलिस ने उनके दो सुरक्षा गार्डों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं खान सर को भी नामजद आरोपी बनाते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. बीते शुक्रवार की रात पुलिस की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए कोचिंग में पहुंची भी लेकिन वहां पर खान सर नहीं मिले. इस दौरान पुलिस का सामना वहां मौजूद छात्रों की भीड़ से पुलिस हुआ. छात्रों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए छात्रों को कोचिंग और उसके आसपास की जगहों से बाहर कर दिया।

खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर हमला

दरअसल इस मामले की शुरुआत 2 जून को राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके से हुई, जहां खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर कुछ लोगों ने हमला और तोड़फोड़ की. इस दौरान कोचिंग संस्थान के सुरक्षा गार्डों ने राइफलों से कई राउंड फायरिंग की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया.

दो सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार

इधर इस विवाद को पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व की लड़ाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस ने जांच के बाद प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इधर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने खान सर के दो सुरक्षा गार्डों प्रदीप और तालेश्वर को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार दोनों ने फायरिंग की बात स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उनके हथियार जब्त कर लिए गए।

खान ग्लोबल स्टडीज में हुई तोड़फोड़ की घटना के संबंध में खान सर पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश की एफआईआर दर्ज होने के बाद से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद क्यों गिरफ्तार हुए?

2 जून की रात खान एकेडमी के बाहर तोड़फोड़, पथराव एवं गार्ड से मारपीट की गई थी। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। खान एकेडमी के मैनेजर ने ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद 3 जून को पुलिस ने रौशन सर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।

पति बेराजगारी का बहाना बनाकर बच नहीं सकता... कोर्ट का भरण-पोषण खर्च देने का आदेश

● 2 जून के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, 'अपने खर्चों का प्रबंधन करना प्रतिवादी यानी पति की जिम्मेदारी है

● वह केवल बेरोजगारी या अन्य जिम्मेदारियों का हवाला देकर अपनी कानूनी रूप से ब्याही पत्नी और नाबालिग बेटे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त नहीं कर सकता

दिल्ली की एक कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में व्यक्ति को फटकार लगाई है. साथ ही निचली अदालत के फैसले को भी पलटा है। कोर्ट ने व्यक्ति को अपने बेटे को 6,000 रुपये मासिक भरण-पोषण देने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि कोई पति बेरोजगार होने का दावा करके अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के प्रति अपनी कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रधान एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रही थीं. महिला ने निचली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (PWDV) अधिनियम' के तहत आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया गया था। जज ने महिला की अपील मंजूर कर ली।

2 जून के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, 'अपने खर्चों का प्रबंधन करना प्रतिवादी यानी पति की जिम्मेदारी है. वह केवल बेरोजगारी या अन्य जिम्मेदारियों का हवाला देकर अपनी कानूनी रूप से ब्याही पत्नी और नाबालिग बेटे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त नहीं कर सकता.' कोर्ट ने पाया कि पति भरण-पोषण का खर्च उठाने में सक्षम है और उसे आदेश दिया कि वह बच्चे के बालिग होने तक उसके भरण-पोषण के लिए हर महीने 6,000 का भुगतान करे।

2013 में शादी और 2015 में हुए अलग

महिला ने आरोप लगाया था कि फरवरी 2013 में उसकी शादी हुई थी, जिसके बाद उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे परेशान किया. उसने दावा किया कि गर्भवती होने के दौरान उसे ससुराल से निकाल दिया गया था और वह 2015 से अपने बेटे के साथ अलग रह रही है. कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, 2015 में फैमिली कोर्ट में हुए समझौते के बाद यह जोड़ा कुछ समय के लिए फिर से साथ रहने लगा था. वे कुछ महीनों तक किराए के घर में रहे लेकिन बाद में फिर अलग हो गए।

महिला की शिकायत कर दी थी खारिज

सितंबर 2025 में, निचली अदालत ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला की शिकायत खारिज कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि वह घरेलू हिंसा और आर्थिक शोषण के आरोपों को साबित करने में नाकाम रही. हालांकि, अपीलीय अदालत ने माना कि शारीरिक हमले और क्रूरता के आरोप मेडिकल रिकॉर्ड या स्वतंत्र सबूतों से साबित नहीं हुए, लेकिन उसने पाया कि पति ने 2015 से बच्चे के भरण-पोषण के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं दी थी. अदालत ने कहा, 'नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी प्रतिवादी (पति) की भी उतनी ही है।'

नाबालिग बेटे के बालिग होने तक दीजिए खर्च

कोर्ट ने यह भी गौर किया कि बच्चा कई सालों से मां की कस्टडी में है और इस दौरान पिता की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई. अदालत ने कहा,'मेरी राय में, प्रतिवादी/पति हर महीने 6,000 का भरण-पोषण खर्च देने में सक्षम है. यह भुगतान इस आदेश की तारीख से शुरू होकर उसके नाबालिग बेटे के बालिग होने (18 साल की उम्र) तक किया जाना चाहिए।

संक्षिप्त ख़बरें

खान सर की बढ़ेंगी मुश्किलें! मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची महिला पत्रकार

खान सर ने टीवी पत्रकार पर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं।

दिल्ली हाई कोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई होगी।

नई दिल्ली। अपमानजनिक टिप्पणियां करने को लेकर टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने खान सर के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अंजना ओम कश्यप द्वारा एक टीवी शो के दौरान स्टार टीचर्स के बढ़ते असर की आलोचना की थी और इसके बाद खान ने अंजना पर तमाम सवाल उठाते हुए टिप्पणियां की थी। मानहानि मुकदमे में अंजाना ने दावा किया कि कई डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रसारित किए गए वीडियो, पोस्ट और ब्राडकास्ट में उनको लेकर बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, और दल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही, उन पर दलाली करने और फेक न्यूज की दुकान चलाने का आरोप भी लगाया गया। अंजाना ओम कश्यप का तर्क है कि इस पोस्ट के कारण उनके परिवार को उत्पीड़न, अवांछित ध्यान और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ा है। याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है।

संविधान नहीं, यूपी पुलिस सत्ता की वफादार... तबादले-पोस्टिंग और प्रमोशन पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

● उत्तर प्रदेश पुलिस और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों की नियुक्ति, तबादले और पदोन्नति अक्सर योग्यता के बजाय राजनीतिक निष्ठा के आधार पर तय होती हैं.

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उत्तर प्रदेश पुलिस और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी संविधान के बजाए सत्ता के प्रति वफादार नजर आ रहे हैं. कई मौकों पर ऐसा होते देखा गया है. कोर्ट ने कहा कि तबादले, पोस्टिंग और प्रमोशन में भी यही चल रहा है. जो पुलिस अधिकारी सत्ता का वफादार है उसे आसानी से ये सब कुछ मिल जाता है. हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण की संस्कृति बहुत गहरी है. राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था लगातार कई सरकारों के शासनकाल में राजनीतिक दखलंदाजी के प्रति संवेदनशील रही है. कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों की नियुक्ति, तबादले और पदोन्नति अक्सर योग्यता के बजाय राजनीतिक निष्ठा के आधार पर तय होती हैं. जबकि इसके लिए योग्यता को तरजीह दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. जस्टिस विनोद दिवाकर की सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज एक मामले की सुनवाई के दौरान की. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और नौकरशाही व्यवस्था लंबे समय से सामंती मानसिकता से प्रभावित रही है, जिसके कारण संवैधानिक शासन कई बार सार्वजनिक सेवा के बजाय व्यक्तिगत प्रभाव और नियंत्रण का माध्यम बन गया है।

राजनीतिक आकाओं के प्रति खुद को ढाल लेते हैं अधिकारी

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में पसंदीदा अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिलों और शहरी कमिश्नरेट में तैनाती दी जाती है, जबकि स्वतंत्र रवैया रखने वाले अधिकारियों को महत्वहीन पदों पर भेज दिया जाता है. अदालत ने कहा कि तबादला-पोस्टिंग की इसी व्यवस्था के कारण कई अधिकारी अपने आचरण को राजनीतिक आकाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप ढाल लेते हैं।

गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गृह विभाग पर भी सवाल उठाए हैं. साथ ही उसकी कार्यप्रणाली को भी आड़े हाथों लिया है. कोर्ट ने कहा कि गृह विभाग भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है. कुछ अधिकारी गृह सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान होकर भी कई निष्पक्ष नहीं दिखाई दिए. उन्होंने कई बार निष्पक्ष प्रशासनिक निर्णयों के बजाय व्यक्तिगत या बाहरी हितों से प्रभावित होकर काम किया. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी कि वह गृह विभाग में कार्यरत अधिकारियों की कार्यक्षमता और उपयुक्ता का स्वतंत्र मुल्यांकन करे, ताकि संस्थागत जवाबदेही तय हो सके।

विकास दुबे कांड का किया जिक्र

हाई कोर्ट ने इतना ही नहीं, कानपुर के बिकरू कांड (विकास दुबे कांड) का भी जिक्र किया. जिसमें कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ था और एक डीएसपी समेत आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी. कोर्ट ने कहा कि इतनी गंभीर प्रशासनिक विफलता के बावजूद संबंधित अधिकारी को केवल औपचारिक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की नरमी संस्थागत दंडमुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देती है, जिससे जवाबदेही कमजोर होती है।

अवैध इमारतों पर दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, खानपुर और सैनिक फार्म्स में चला एमसीडी का हथौड़ा

● मालवीय नगर अग्निकांड के बाद कार्रवाई तेज।

● MCD ने अवैध बहुमंजिला इमारतों पर की तोड़फोड़।

● खानपुर, सैनिक फार्म्स में चला ध्वस्तीकरण अभियान।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। मालवीय नगर अग्निकांड और सैदुलाजाब में इमारत गिरने की घटनाओं के बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी ने अवैध बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई तेज कर दी है। दक्षिण दिल्ली के कृष्णा पार्क इलाके में रविवार को एम सी डी की टीम ने एक बहुमंजिला इमारत पर हथौड़ा चलाया। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार नियमों की अनदेखी कर बनाए गए निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। रविवार को खानपुर और सैनिक फार्म्स में अवैध बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस एक्शन की सराहना करते हुए बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने सीएम रेखा गुप्ता की तारीफ की।

150 से अधिक अवैध निर्माणों को हटाया गया

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्लीवासियों की सुरक्षा और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इससे पहले शालीमार बाग (हैदरपुर) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सड़क चौड़ीकरण के लिए 150 से अधिक अवैध निर्माणों को हटाया गया था।

एम सी डी ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध विशेष 'क्रैकडाउन' अभियान शुरू

मालवीय नगर आग त्रासदी और सैदुलाजाब इमारत हादसे के बाद उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली सरकार, राजस्व विभाग और एम सी डी ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध विशेष 'क्रैकडाउन' अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राजधानी में लगातार चेकिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

कैंसर अधिसूचित करने लायक बीमारी नहीं... सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर केंद्र का जवाब

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कैंसर को संक्रामक रोगों की तरह अनिवार्य रूप से अधिसूचित करने लायक बीमारी नहीं है. ना ही ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि यह एक गैर-संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है. केंद्र ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कही है. दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अनुराग श्रीवास्तव की रिट याचिका पर जारी नोटिस के जवाब में हलफनामा दाखिल किया है. याचिका में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कैंसर को अधिसूचित बीमारी की सूची में डालने और निगरानी से संबंधित उपायों की मांग की गई है. जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) संक्रामक रोगों के लिए बनाई गई अनिवार्य अधिसूचना प्रणाली के बजाय कैंसर को रजिस्टर करने और दीर्घकालिक महामारी विज्ञान के तहत निगरानी की सिफारिश करता है. वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया और कहा कि देश में कैंसर रोग को प्रबंधित करने के लिए मौजूदा तंत्र वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त और संवैधानिक रूप से अनुपालन योग्य हैं।

कैंसर स्वास्थ्य संविधान के अंतर्गत राज्य का विषय

केंद्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि कैंसर संक्रामक नहीं है और इससे सामुदायिक प्रसार का कोई खतरा नहीं है. हलफनामे में कहा गया है कि स्वास्थ्य संविधान के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्य का विषय है, और रोग अधिसूचना संबंधी निर्णय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों या कार्यकारी आदेशों के तहत कैंसर को निगरानी के लिए अधिसूचित कर दिया है. जबकि आईसीएमआर द्वारा राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (NCRP) और संबंधित जनसंख्या-आधारित और अस्पताल-आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी कैंसर निगरानी पहले से ही की जा रही है।

नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप न करने का आग्रह

सरकार ने हलफनामे में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD), आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई, राज्य कैंसर संस्थान और तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्र समेत मौजूदा समय चल रही कई पहलों पर प्रकाश डाला और कहा कि ये कार्यक्रम कैंसर की रोकथाम, स्क्रीनिंग, निदान और उपचार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

अमईपार के भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे दबंग BDO कुदरहा आलोक कुमार पंकज

● BDO आलोक कुमार पंकज द्वारा अमईपार के ग्राम प्रधान कृष्णा मुरारी शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए दिया जा रहा संरक्षण

ग्राम प्रधान कृष्ण मुरारी शुक्ला ने 27 जून को पूर्ण फर्जी मस्टर रोल को करा लिया है फीड 05 जून को पूर्ण फर्जी मस्टर रोल फीड कराने के फिराक में जुटे

भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे BDO आलोक कुमार पंकज की मनमानी से ग्राम पंचायत अमईपार में भ्रष्टाचार का बन रहा रिकार्ड

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बस्ती। बस्ती जिले केकुदरहा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अमईपार में मनरेगा घोटाला अब अंतिम चरण में है। तालाब खुदाई के नाम पर 2 फर्जी ऑनलाइन मस्टर रोल जारी हुए थे - पहला 27 मई को पूर्ण हो चुका, दूसरा 05 जून को पूर्ण हो गया है। खण्ड विकास अधिकारी आलोक कुमार पंकज ग्राम पंचायत अमईपार के भ्रष्टाचार के दलदल में धंसते दिखाई दे रहे हैं। बीडीओ की मनमानी से भ्रष्टाचारी ग्राम पंचायत कृष्ण मुरारी शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई नही हो पा रही है जिससे भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधान का मनोबढ़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधान ने 27 मई के पूर्ण फर्जी मस्टर रोल को सचिव , टीए , मनरेगा एपीओ व कम्प्यूटर ऑपरेटर को मुंहमांगा कमीशन देकर आइनलाइन भुगतान हेतु फीड करा दिया है और पुनः 05 जून को पूर्ण फर्जी आइलाइन मस्टर रोल को भुगतान के लिए फीड कराने के फिराक में है।

भुगतान का गणित– सबसे खतरनाक स्टेज:

1. **222 फर्जी मजदूर:** दोनों मस्टर रोल पर 222-222 मजदूरों की फर्जी हाजिरी रोजगार सेवक रानी बाला लगा रही हैं
2. **55 हजार रोज:** दोनों मस्टर रोल मिलाकर रोज ?55,000+ की फर्जी हाजिरी
3. भुगतान की फिराक: ग्राम प्रधान कृष्ण मुरारी शुक्ला TA, सचिव, APO, कंप्यूटर ऑपरेटर को मुंहमांगा कमीशन देकर फर्जी MB कराने में जुटे हैं
4. **BDO की परीक्षा:** खण्ड विकास अधिकारी कुदरहा आलोक कुमार पंकज के लिए चुनौती है कि 27 मई वाला फर्जी मस्टर रोल का भुगतान रोकें और 5 जून को पूर्ण मस्टर रोल भुगतान के लिए रोके।

सिस्टम का हाल: आरोप है कि ष्ठष्ट मनरेगा संजय शर्मा ष्ठ्र ष्ट में बैठकर ठंडी हवा ले रहे हैं। अगर अभी संज्ञान नहीं लिया गया तो ग्राम प्रधान फर्जी भुगतान में बाजी मार जाएंगे।

5 जून से पहले ये करना जरूरी है: फर्जी मस्टर रोल का भुगतान रोकने के लिए 100% सत्यापन अनिवार्य है। भुगतान हो गया तो रिकवरी मुश्किल हो जाती है।

अभी तुरंत कार्रवाई के लिए:

1. BDO कुदरहा आलोक कुमार पंकज- दोनों मस्टर रोल नंबर लिखकर भुगतान पर तत्काल रोक लगाएं। 27 मई वाले स्न्क्र की जांच कराएं।
2. CDO सार्थक अग्रवाल- 222 फर्जी मजदूरों के मामले में हस्तक्षेप। फेस हाजिरी फोटो व जियो-टैग चेक कराएं।
3. लोकपाल, मनरेगा बस्ती- फर्जी स्न्क्र पर रोक + ग्राम प्रधान कृष्ण मुरारी शुक्ला, रोजगार सेवक रानी बाला, TA, सचिव, APO, कंप्यूटर ऑपरेटर पर FIR की मांग
4. DM बस्ती- मनरेगा एक्ट को खुलेआम पलीता लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई 5. CM हेल्पलाइन 1076 - '5 जून को अमईपार का फर्जी स्न्क्रपूर्ण हो रहा, भुगतान रोकें '

कानून: फर्जी MB और फर्जी भुगतान IPC 420, 467, 409 के तहत 7 साल तक जेल है। भुगतान से पहले रोक देना ही असली कार्रवाई है। अब देखना यह है कि उक्त प्रकरण में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है ?

भारत की विकास यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महती भूमिका

भारत आज दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। जब देशवासी अपने देश की तरक्की की बातें सुनते हैं तो बेशक उन्हें बड़ी खुशी और गर्व होता है। भारत की इस विकास यात्रा में केंद्र व राज्यों की सरकारों के साथ-साथ देश के नागरिकों का भी अपना अथाह योगदान है, तभी तो आज हम दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनकर उभर रहे हैं। भारत की विकास यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी महती रही है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। बेशक कुछ संघ-विरोधी विचारधारा वाले लोगों को देश की विकास यात्रा में संघ का योगदान अचरज भरा भी लगे, किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को यह देश कभी भुला नहीं पाएगा। आजादी के उस वक्त को याद कर कल्पना करें, कुछ तथाकथित सत्ता-स्वार्थी राजनेताओं की हुक्मरान बनने की चाहत के चलते जिस देश की आजादी धर्म के नाम पर की गई हो, वहाँ कितना खून-खराबा अपनों का अपनों के ही हाथों हुआ होगा? पाकिस्तान के उदय के साथ ही लाहौर से लेकर कराची तक, पूर्वी-पश्चिमी सीमाओं तक बसने वाले हिंदुओं के कत्लेआम की जो दास्तां देश ने देखी है, उसकी कल्पना मात्र से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है।

आजादी से पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत की कल्पना को साकार करने की अलख जगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा था। कई मौकों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता और तत्कालीन प्रथम सरसंघचालक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार और द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर 'गुरुजी' ने भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सभी बड़े तत्कालीन नेताओं से अखंड भारत बनाए रखने की लड़ाई लड़ने की बात कही, लेकिन संघ विरोधी मानसिकता वाले कुछ लोगों ने हर बार संघ की बातों को नजरअंदाज करते हुए मुस्लिम लीग के जिन्ना की जिद के आगे नतमस्तक होकर आखिरकार अखंड भारत को धर्म के नाम पर टुकड़ों में बांट दिया था। जिन्ना की मुस्लिम लीग के समर्थक गुंडों और पाकिस्तानी फौजी सिपाहियों ने पाकिस्तान के हर हिस्से में रह रहे हिंदुओं को वहाँ से भागने के लिए उन पर रक्तरंजित अत्याचार ही नहीं किए, बल्कि हिंदू बेटियों, बहुओं और माताओं की अस्मिता को भी सरेआम लूटकर तार-तार किया था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की लाशों के ढेर इस बात के सबूत थे कि हिंदुओं के प्रति जिन्ना और उसके गुंडों ने सत्ता की लालच में लोगों के बीच कितना जहर भरा था। आजादी के उस रक्तरंजित दौर में पाकिस्तान में सबसे पहले हिंदू माँ-बहनों और बेटियों की अस्मिता को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ही आगे आए और जिन्ना के गुंडों तथा उसके सिपाहियों से अपनी जान की बाजी लगाकर जितना हो सकता था, उतने हिंदुओं को बचाने का भरसक प्रयास भी किया था। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विभाजन की त्रासदी से अपनी ही जमीन से बेदखल किए गए हिंदुओं की मदद हेतु जगह-जगह राहत शिविर खोलकर पाकिस्तान से बेदखल और प्रताड़ित किए गए हिंदुओं तथा उनके परिजनों को न केवल सुरक्षा दी, बल्कि स्वयंसेवकों ने बिना सरकारी मदद के अपने दम पर महीनों तक उन हिंदुओं के भोजन, पानी और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की थी। यह तो देश जानता है कि विभाजन के उस कठिन दौर में कैसे आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को बचाया था। आजादी के दौर के बहुत से लोगों का मानना है कि यदि आजादी के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाते, तो जिन्ना के गुंडे और गुंडागर्दी पर उतारू उसकी सेना नफरत की आग में पाकिस्तान से समूची हिंदू कौम का ही सर्वनाश कर देते।

देश की आजादी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीयों में एकजुटता बनी रहे, इस महान उद्देश्य को लेकर बिना प्रचार-प्रसार के अपने कार्यकर्ताओं के बूते अलख जगाए रखी, जिसकी परिणति यह है कि भारत आज दुनिया की महाशक्तियों को अपने आगे झुकाने वाला देश बन गया है। देश में जब-जब भी विपदाएँ आई, तब-तब सरकार से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से अपनी जान की परवाह किए बिना विपदाओं में उम्मीदों का सहारा बनकर खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए गए कार्यों की विपक्ष के नेता तक खुले मन से प्रशंसा करते रहे हैं। देश में जब भी कहीं भीषण बाढ़ आई हो, सूखा पड़ा हो, भूकंप की त्रासदी हुई हो या फिर कोई गंभीर बीमारी ही क्यों न फैली हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता देश में आई हर विपदा में सबसे पहले सहारा बनकर खड़ा हो जाता है और बिना जाति-धर्म पूछे अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा कार्यों में जुट जाता है।

आरएसएस देश को जोड़ने और मजबूती प्रदान करने वाला संगठन है, जो बिना जाति-धर्म का भेद किए देश के हर वर्ग और समाज के विकास में सहयोग प्रदान करता है। आरएसएस का दायरा समूचा देश और देश में रहने वाले सभी जाति-धर्मों के लोगों के बीच मानवीय प्रेम और राष्ट्रीय एकता बनी रहे, इसी महान उद्देश्य को लेकर दिन-रात उसके स्वयंसेवक कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकमात्र ऐसा संगठन है, जो अपने किए गए कार्यों का कभी दिखावा नहीं करता और न कभी अपना बखान करता है। देश की सेहत देखकर ही संघ की सक्रियता समझी जा सकती है। देश यदि आज दुनिया में सिरमौर बन रहा है, तो इसमें आरएसएस की भूमिका को भी खुले मन से स्वीकारना होगा। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रहित को समर्पित संगठन आरएसएस के करोड़ों कार्यकर्ता बेहद अनुशासित तरीके से अपने सरसंघचालक के हर शब्द को अपना सर्वस्व त्याग कर निस्वार्थ भाव से पूर्ण करते हैं। यह संघ के सरसंघचालक के तपोबल का ही परिणाम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री मोहन भागवत छठे सरसंघचालक हैं। इससे पूर्व डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, मधुकर दत्तात्रेय देवरस, प्रो. राजेंद्र सिंह 'रज्जू भैया' और के. एस. सुदर्शन जी के त्याग और अनुशासन से संघ दुनिया भर के देशों में अपनी जड़ें मजबूती से जमाए हुए मानवीय सेवा के कार्यों हेतु समर्पित है।

भारतीय राजनीति के कुछ अवसरवादी सत्ता-स्वार्थी नेताओं ने अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आरएसएस को देश-विरोधी संगठन बताने से भी गुरेज नहीं किया है। इतना ही नहीं, कुछ राजनीतिक दलों ने सत्ता में आने के बाद जाति-धर्म के वोट बैंक के सहारे सत्ता में बने रहने की चाहत में अपने-अपने राज्यों में आरएसएस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था और आरएसएस से संबंध रखने वाले भारतीयों को प्रताड़ित भी किया जाता था। देश के कुछ राज्यों में आज भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर बंदिशें लगाई गई हैं। वर्तमान में राजनीति से जुड़े कुछ लोगों ने एक विशेष वर्ग के वोट बैंक पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आरएसएस को केवल हिंदुओं का संगठन बता कर उसके खिलाफ आए दिन जहर उगला है। बेशक आरएसएस एक हिंदुत्ववादी विचारधारा वाला संगठन है, जिसका महान उद्देश्य सभी धर्मों और जातियों के लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत कर राष्ट्र को एकजुट और मजबूत बनाना है।

आरएसएस की विचारधारा के विरोधी जो भी लोग आज राजनीति में मौजूद होकर जात-पात की राजनीति करते हैं, उन्हें देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखना चाहिए कि उन्होंने देशहित के कार्यों में आरएसएस की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समय-समय पर प्रशंसा भी की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघचालक श्री मोहन भागवत देश के सभी वर्गों और धर्मों के प्रमुखों के साथ मिलकर संघ के प्रति राजनीतिक दलों द्वारा जो दूषित धारणाएँ फैलाई गई थीं, उन्हें बहुत हद तक दूर कर संघ के सच्चे राष्ट्र हित के उद्देश्य से परिचित करवाकर अन्य धर्मों को भी संघ की विचारधारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। देश इस वर्ष विजयादशमी के अवसर पर आरएसएस की स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के मार्गदर्शन में देशभर में संघ के कार्यों से देश की नई पीढ़ी को अवगत कराने के कार्यक्रम जारी हैं। आरएसएस एक ऐसा सामाजिक संगठन है, जो जाति-धर्म के नाम पर टुकड़ों में बंटे और बिखरे लोगों को एकजुट करता है तथा उनमें अपने राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक का पाठ सिखाता है।

आरएसएस की स्थापना भी सन 1925 में विजयादशमी के दिन डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार जी द्वारा इसी महान उद्देश्य को लेकर की गई थी। अपने सौ वर्षों के सफर में आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण, त्याग और अनुशासन के बल पर आज एक वटवृक्ष बनकर दुनिया के अस्सी से ज्यादा देशों में फैल चुका है।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक श्री मोहन भागवत की अगुवाई में संघ अपना सौवां जन्मोत्सव पिछली विजयादशमी को मनाया गया उस ऐतिहासिक पल का समूचा दे साक्षी बना! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को पूरे वर्ष देशभर में हर्षोल्लास से मनाएगा और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के विकास में संघ की भूमिका से उसके त्याग बलिदान और कर्तव्य निष्ठा से नवपीढ़ी को परिचित भी करवाएगा।

अरविंद रावल

युवाओं के भविष्य पर डाका: पेपर लीक, अरबों का खेल और 'उम्मीदों' का अंतहीन स्कैम

संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला

आज के दौर में देश के युवाओं के साथ होने वाला सबसे बड़ा और संगठित स्कैम 'पेपर लीक' बन चुका है। यह संकट सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने भर का नहीं है, बल्कि इसके पीछे करोड़ों युवाओं के सपनों, समय और उनके परिवारों की गाढ़ी कमाई की सुनियोजित लूट का एक ऐसा चक्रव्यूह है, जिसका सच बेहद खौफनाक है।

100 करोड़ का गणित: आवेदन के नाम पर धन-उगाही

यदि पुलिस और चुनिंदा शिक्षक भर्तियों को छोड़ दिया जाए, तो अमूमन किसी भी विभाग में 500 से अधिक पद नहीं निकलते। चतुर्थ श्रेणी या लेखपाल जैसी भर्तियों का उदाहरण लें, तो चंद सौ या हजार पदों के लिए 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आवेदन आते हैं। यह स्थिति स्वतः स्पष्ट करती है कि 99% से अधिक आवेदकों के हिस्से सिर्फ असफलता ही आनी है। लेकिन खेल इसके पीछे के 'परीक्षा शुल्क' का है। यदि प्रति छात्र औसतन 400 रुपये भी फीस मानी जाए और 25 लाख आवेदन आएं, तो यह रकम **100 करोड़ रुपये** बनती है। तमाशा देखिए:पेपर लीक होता है, परीक्षा रद्द होती है। युवा अपना समय, किराया और उम्मीदें गंवाकर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी आयोग के अध्यक्ष को अपना पूरा वेतन मिल चुका होता है और परीक्षा कराने वाली प्राइवेट एजेंसियां अपना 80% तक भुगतान डकार चुकी होती हैं। नुकसान हुआ तो सिर्फ देश के युवा का।

कोचिंग हब: असफलता को भुनाने वाला बाज़ार

इस बड़े असफल समूह को निशाना बनाकर आज देश में अरबों रुपयों का 'कोचिंग व्यवसाय' खड़ा किया गया है। कोचिंग संस्थान भी भली-भांति जानते हैं कि नौकरियां चुनिंदा लोगों को ही मिलनी हैं। इसलिए, अपनी साख बचाने के लिए ये संस्थान दोहरी चाल चलते हैं:

परीक्षा से पहले: कई बार व्यवस्था में सेंध लगाने या अनुचित लाभ उठाने के प्रयास।

परीक्षा के बाद: गड़बड़ी का बढ़-चढ़कर प्रचार, ताकि जब छात्र असफल हों, तो उनका ध्यान कोचिंग की नाकामी से हटकर व्यवस्था की कमी पर चला जाए।

यह सरकारी तंत्र को क्लीन चिट देने का बहाना नहीं है, बल्कि यह समझने का जरिया है कि युवा चारों तरफ से बिचौलियों से घिरा हुआ है।

बुनियाद पर चोट: सरकारी बनाम निजी स्कूलों का गोरखधंधा

इस स्कैम की जड़ें और गहरी तब हो जाती हैं जब हम स्कूली शिक्षा के स्तर पर देखते हैं। सरकारी विद्यालयों के विलय (Merger) की नीति एक बड़ी सामाजिक समस्या बन रही है। गाँवों के स्कूल बंद होने से गरीब परिवारों के बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, शिक्षा से महरूम हो रही हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों से लोग बेटियों को दूर के स्कूलों में भेजने से कतराते हैं। दूसरी ओर, निजी स्कूलों का एक बड़ा गोरखधंधा चल रहा है। अधिकांश बड़े निजी शिक्षण संस्थानों के पीछे किसी न किसी रसूखदार 'नेताजी' का हाथ होता है। अब ज़रा सोचिए:

एक तरफ सरकारी स्कूल से सिर्फ 'साक्षर होने वाला गरीब का बच्चा है। दूसरी तरफ महंगे निजी स्कूल से 'शिक्षित' होने वाला अमीर का बच्चा है। जब इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा (Competition) कराई जाएगी, तो परिणाम पहले से तय है। अमीर और अमीर होता जाएगा, और गरीब का बच्चा उसी दुष्चक्र में फंसा रहेगा।

राजनीति का मौन और अंतिम धोखा

यदि इन तमाम झंझावातों, असमानताओं और अभावों को पार करके कोई गरीब या मध्यमवर्गीय युवा भर्ती परीक्षा तक पहुंच भी जाता है, तो वहाँ उसे 'पेपर लीक' का अंतिम और सबसे क्रूर धोखा मिलता है। फॉर्म भरने से लेकर कोचिंग की फीस और शहरों में रहने के खर्च के नाम पर लाखों रुपये गंवाने के बाद युवाओं के हिस्से केवल निराशा या फिर से 'जीरो' से तैयारी करने की मजबूरी आती है। इस पूरे तंत्र में सिस्टम के शीर्ष पर बैठे लोग सुरक्षित हैं–आयोग के अध्यक्ष अपना वेतन लेते हैं, राजनेता रैलियों में अपनी पीठ थपथपाते हैं और निजी एजेंसियां अपना मुनाफा समेटती हैं। पेपर लीक जैसे संवेदनशील और युवाओं के जीवन को तबाह करने वाले मुद्दों पर सत्ताधीशों का मौन या ढीला रवैया यह साफ संकेत देता है कि इस सामूहिक लूट का कोई न कोई सिरा व्यवस्था के रक्षकों को भी पोषित कर रहा है। यह धोखा सिर्फ एक छात्र को नहीं, बल्कि सीधे इस देश के भविष्य को दिया जा रहा है।

भारतवर्ष की गुरु-शिष्य सनातनी परंपरा, देश के प्रति समर्पण भाव

राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रवाद शालाओं की बुनियादी शिक्षा कक्षाओं और गुरु और शिष्य परंपरा के साथ देश के प्रति समर्पण के भाव से प्रस्फुटित होता हैद्य राष्ट्रवाद राष्ट्र की रक्षा ,अखंडता एवं सशक्तिकरण नागरिकों के भाग्य को संरक्षित कर सुदृढ़ बनाता हैद्य स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के स्वप्न दृष्टा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के भावी भविष्य को पहचानते हुए बुनियादी कक्षाओं की राष्ट्रवाद के निर्माण में भूमिका को सहजता से पहचान लिया और अमेरिका की तर्ज पर भारत को तकनीकी तौर पर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए अमेरिका के एमआईटी की तर्ज पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करवाया था ।जब खड़कपुर आईआईटी की स्थापना की गई थी तब उन्होंने अतिथि के रूप में अपने भाषण में कहा की भारत को वैज्ञानिक महाशक्ति बनाने का दायित्व इन्हीं आई,आई,टी की कक्षाओं शिक्षकों एवं छात्राओं का होगा, वे राष्ट्र को तकनीकी दिशा में मील का पत्थर बनाने में साबित होंगे। वर्तमान में भारत आज अंतरिक्ष की बड़ी शक्तियों की कतार में शामिल हैद्य इसके पीछे भारत के कई वैज्ञानिक सीवी रमन, विक्रम साराभाई, सतीश धवन जैसे बड़े वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इसरो संस्थान है जिसकी कक्षाओं में मंगल तक भारतीय तिरंगे को लहराया. भाभा एटॉमिक परमाणु शक्ति बन गया हैद्य वैश्विक स्तर पर हर बड़े स्पेस रिसर्च सेंटर पर भारत की इंजीनियर और वैज्ञानिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

आज अमेरिका आर्थिक महाशक्ति बनने के पीछे उसके विश्वविद्यालय ,संस्थाएं हैं। हावर्ड बिजनेस स्कूल विश्व स्तरीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में से एक माना जाता हैद्य आर्थिक सामाजिक तथा वैज्ञानिक शोध संस्थाओं में अधिकाधिक धनराशि खर्च करके अमेरिका, रूस, ब्रिटेन ,चीन, ऑस्ट्रेलिया ,कनाडा ने विश्व में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी दिए हैंद्य यह तो तय है कि कोई भी देश का भाग्य तभी उन्नत तथा विकसित होगा जब वहां के छात्र शिक्षक एवं आमजन न्याय, समता ,प्रबुद्धता के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता रखें। आने वाली पीढ़ी यानी कि वर्तमान के बच्चे और भविष्य के नागरिक ही किसी देश का भविष्य निर्माण करते हैं और यह भी तय रहता है कि बुद्धिमान शिक्षक अपने छात्रों के माध्यम से किसी महान राष्ट्र की नींव रखते हैं।

किसी भी महान राष्ट्र का निर्माण रातों-रात नहीं होता है इसके लिए पीढीयो का योगदान और श्रेष्ठ शिक्षक एवं छात्रों की लग्न शीलता और मेहनत की प्रतिबद्धता होती है। 1960 और 70 के दशक में चीन में गठित सांस्कृतिक क्रांति कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, खेतों, कारखानों को एकता में बांधकर सक्रिय नीति का प्रयोग कर सभी को एक सूत्र में बांधा गया था। जापान तो प्राथमिक कक्षाओं से उपजे राष्ट्रवाद, अनुशासन तथा कर्तव्य बोध के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा है, जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पराजय का कड़वा घूंट पीने के पश्चात कमजोर एवं मृतप्राय जापान को एक शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र बना दिया। इसके विपरीत वर्तमान कक्षाएं प्रेम, अनुशासन ,करुणा जैसे पाठ ना सिखा कर ईर्ष्या, कंपटीशन, हिंसा, कटुता जैसे अध्याय सिखा कर राष्ट्र के भविष्य को गर्त में ले जा रही है। देश के अनेक विश्वविद्यालय हड़ताल, हिंसा, जाति भेदभाव, आपत्तिजनक नारों जैसे विसंगतियों का सामना कर रहे हैं। कक्षाओं का नैतिकता, सहिष्णुता ,अनुशासन से कटाव केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में इसका फैलाव हो चुका है। अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में स्कूलों का कक्षाओं में गोली कांड इसके बड़े विकृत उदाहरण हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ट्रीस्ट विद डेस्टिनी के भाषण में भूख, भय ,बीमारी, अज्ञान से पूर्णता मुक्ति की बात को भारत की नियति या डेस्टिनी कहा है।

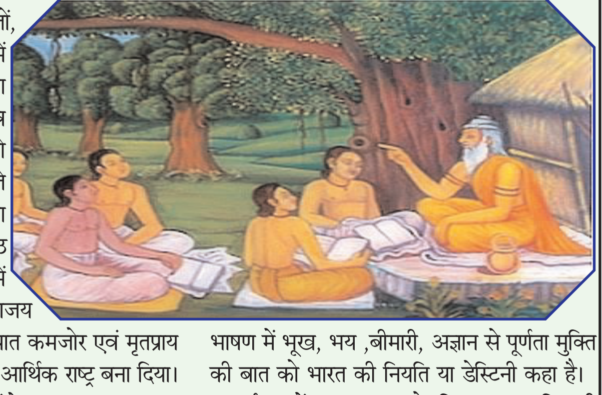

वर्तमान में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए की कक्षाओं को चरित्र निर्माण, अनुशासन, उत्कृष्ट नवाचार, लोकतांत्रिक विचार संरचना का केंद्र बनाकर इसकी शिक्षा दीक्षा दी जानी चाहिए। कक्षाओं से बच्चे आर्थिक रूप से प्रौद्योगिकी स्थापित कर स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर आने वाले वर्षों में कई युवाओं को रोजगार देकर संपूर्ण मानवता ,पर्यावरण की रक्षा तथा राष्ट्र के उत्कर्ष को सही दिशा देने का काम करेंगे। जिससे राष्ट्रीय चरित्र निर्माण तथा राष्ट्रीयता की भावना को एक मजबूत आधार प्राप्त हो सकेगा।

संजीव ठाकुर

कविता

पत्तों की शाखों पर जैसे सावन ठहरता रहा,
बंद किताब के पन्नों में तेरा चेहरा संवरता रहा।

रातों में झाँकती रहीं यादों की चुप चाँदनियाँ,
मन के सूने आँगन में जैसे दीप उतरता रहा।

साँसों की सरगम में घुलती मधुर स्वर लहरी,
तेरा नाम मेरे अधरों पर धीमे धीमे निखरता रहा।

धूप ने लाख बिछाए राहों में तपते पत्थर,
प्रेम का नन्हा सावन साथ गुजरता रहा।

आँखों में सपनों की नैया लहरों पर तैरती रही ,
विश्वास का तिनका तूफ़ाँ से उबरता रहा।

मौसम ने बदली बार बार अपनी करवट,
तेरा स्नेह मन में बादल बन बरसता रहा।

रिश्ते शब्दों से बढ़कर मौन में जी लेते,
अनकहा अपनापन हमें सँवारता रहा।

वक़्त की तेज़ हवाओं ने कितने पत्ते बिखराए,
स्मृतियों का सूखा पत्ता फिर भी निखरता रहा।

जब जीवन की राहों में अँधियारा गहराया,
तेरा चेहरा चांदनी में रात उभरता रहा।

'संजीव' हृदय की बस्ती में प्रेम अमर हुआ,
जग बदलता रहा पर रिश्ता निखरता रहा।

संजीव ठाकुर

नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज होने जा रहा एक नया रिकॉर्ड

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यहाँ जनता समय-समय पर अपने नेताओं का चयन करती है और सत्ता परिवर्तन के माध्यम से लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाती है। स्वतंत्रता के बाद से देश ने अनेक प्रधानमंत्रियों को देखा, लेकिन कुछ नेता ऐसे रहे जिन्होंने केवल शासन नहीं किया बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा और स्वरूप को भी गहराई से प्रभावित किया। जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के बाद यदि किसी प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा है तो वह नरेंद्र मोदी हैं। 10 जून 2026 का दिन इसी कारण राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे रिकॉर्ड के साथ चर्चा के केंद्र में होंगे जो भारतीय राजनीति में उनके लंबे और प्रभावशाली सफर का प्रतीक माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। यह जीत इसलिए ऐतिहासिक थी क्योंकि लगभग 30 वर्षों बाद किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। उस दौर में देश भ्रष्टाचार, आर्थिक सुस्ती और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दों से जूझ रहा था। जनता एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में थी जो निर्णायक दिखाई दे और देश को नई दिशा दे सके। नरेंद्र मोदी ने विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व के नारों के साथ चुनाव अभियान चलाया और जनता ने उन्हें भारी समर्थन दिया।

2014 की जीत केवल एक चुनावी विजय नहीं थी बल्कि भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत थी। लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहने वाली कांग्रेस पार्टी पहली बार इतनी कमजोर स्थिति में पहुँच गई। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इस परिवर्तन का मुख्य केंद्र बन गया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान पहले से ही एक विकासवादी नेता की बन चुकी थी और उसी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार मिला। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया। सामान्यतः किसी सरकार के 5 वर्षों के बाद सत्ता विरोधी लहर देखी जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पहले से भी अधिक सीटें जीत लीं। इस विजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि मोदी केवल एक लोकप्रिय नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुके हैं। 2019 की जीत के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उनकी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनका व्यापक राजनीतिक प्रभाव पड़ा।

2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगातार तीन बार सत्ता में लौटना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आसान नहीं होता। इसके लिए केवल चुनावी रणनीति ही नहीं बल्कि व्यापक जनसमर्थन, मजबूत संगठन और प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मोदी की तीसरी पारी को भारतीय राजनीति के बड़े घटनाक्रमों में गिना जाता है। 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन को लेकर चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि वे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने वाले नेताओं की सूची में और अधिक मजबूत स्थिति प्राप्त करेंगे। भारतीय राजनीति में लंबे कार्यकाल का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र में जनता हर चुनाव में सरकार को बदलने का अधिकार रखती है। ऐसे में यदि कोई नेता लगातार वर्षों तक जनता का समर्थन बनाए रखता है तो यह उसकी राजनीतिक क्षमता और जनस्वीकार्यता को दर्शाता है।

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू लगभग 16 वर्ष 286 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। यह रिकॉर्ड आज भी सबसे लंबा लगातार प्रधानमंत्रित्व माना जाता है। नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश का नेतृत्व किया। उनके सामने विभाजन की त्रासदी, आर्थिक कमजोरी, संस्थाओं के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय पहचान जैसी अनेक चुनौतियाँ थीं। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव मजबूत करने, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास किया। आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने जब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उनके सामने चुनौती थी कि भारत को आर्थिक, सामरिक और तकनीकी दृष्टि से और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। मोदी ने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और मजबूत नेतृत्व को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने विदेश नीति में भी सक्रियता दिखाई। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को नई गति मिली। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली दिखाई देने लगी।

मोदी सरकार के दौरान अनेक कल्याणकारी योजनाएँ भी शुरू की गईं। जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। आयुष्मान योजना के जरिए गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का प्रयास हुआ। स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त राशन योजना ने करोड़ों लोगों को राहत दी। इन योजनाओं ने गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के बीच मोदी सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार की आलोचना भी करता रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कई विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक असमानता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराना आने वाले समय में सरकार के सामने सबसे कठिन कार्यों में से एक होगा। किसान आंदोलन ने भी यह दिखाया कि बड़े जनसमूह सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद नरेंद्र मोदी की राजनीतिक लोकप्रियता लंबे समय तक बनी रही।

भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति भी मोदी की सफलता का एक बड़ा कारण रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का विशाल कार्यकर्ता तंत्र बूथ स्तर तक सक्रिय रहता है। चुनाव प्रबंधन, प्रचार अभियान और मतदाताओं तक सीधा संपर्क भाजपा की विशेषता बन चुके हैं। इसके अलावा विपक्ष की एकजुटता की कमी ने भी भाजपा को लाभ पहुँचाया। कई राज्यों में विपक्षी दल आपसी मतभेदों के कारण मजबूत चुनौती प्रस्तुत नहीं कर सके। आधुनिक राजनीति में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता ने उन्हें युवाओं और नए मतदाताओं से सीधे जोड़ने में सहायता की। रेडियो कार्यक्रमों, वीडियो संदेशों और विशाल जनसभाओं के माध्यम से उन्होंने लगातार जनता के साथ संवाद बनाए रखा। यह शैली पहले के प्रधानमंत्रियों से अलग मानी जाती है। नेहरू के समय में संचार के साधन सीमित थे, जबकि आज राजनीति का बड़ा हिस्सा डिजिटल मंचों पर भी संचालित होता है।

इतिहास केवल आँकड़ों से नहीं बनता बल्कि जनमानस की स्मृतियों से भी बनता है। जवाहर लाल नेहरू को आधुनिक भारत की संस्थाओं के निर्माण के लिए याद किया जाता है। इंदिरा गांधी को निर्णायक नेतृत्व और राजनीतिक साहस के लिए जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को संवाद और सहमति की राजनीति का प्रतीक माना जाता है। नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बनी है जिसने भारतीय राजनीति को अत्यधिक केंद्रीकृत नेतृत्व की दिशा दी और राष्ट्रवाद को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया। 10 जून 2026 का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह दिन भारतीय राजनीति में नेतृत्व की निरंतरता और बदलते जनादेश दोनों का प्रतीक बन रहा है। लोकतंत्र में लंबे समय तक सत्ता में बने रहना असाधारण उपलब्धि माना जाता है। यह केवल चुनावी जीत नहीं बल्कि जनता के विश्वास का संकेत भी होता है। नरेंद्र मोदी के समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व की विजय मानते हैं, जबकि आलोचक इसे भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व आधारित राजनीति के बढ़ते प्रभाव के रूप में देखते हैं। लेकिन दोनों पक्ष इस बात से सहमत दिखाई देते हैं कि पिछले एक दशक से अधिक समय में भारतीय राजनीति का केंद्र नरेंद्र मोदी ही रहे हैं।

भविष्य में इतिहास नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का मूल्यांकन कई आधारों पर करेगा। आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, विदेश नीति की उपलब्धियाँ और आम नागरिक के जीवन में आए बदलाव इन सबके आधार पर उनके शासन को परखा जाएगा। यदि आने वाले वर्षों में भारत आर्थिक और तकनीकी शक्ति के रूप में और मजबूत होता है तो मोदी के कार्यकाल को विशेष महत्व दिया जाएगा। वहीं यदि बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असंतोष जैसी समस्याएँ बढ़ती हैं तो आलोचनाएँ भी तेज होंगी। यही लोकतंत्र की विशेषता है कि किसी भी नेता का अंतिम मूल्यांकन इतिहास और जनता दोनों मिलकर करते हैं। इस प्रकार 10 जून 2026 केवल एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक बनने जा रही है। यह दिन उस राजनीतिक यात्रा की याद दिलाता है जिसमें एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति देश का सबसे प्रभावशाली नेता बनता है और लगातार वर्षों तक सत्ता में बना रहता है। नेहरू से मोदी तक की यह यात्रा भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, जनता के बदलते विश्वास और नेतृत्व की निरंतर बदलती परिभाषा को भी दर्शाती है। भारतीय राजनीति में रिकॉर्ड बनते और टूटते रहेंगे, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो इतिहास में स्थायी रूप से दर्ज हो जाते हैं। 10 जून 2026 को लेकर चल रही चर्चा भी भारतीय लोकतंत्र के ऐसे ही एक ऐतिहासिक क्षण की ओर संकेत करती है।

महेन्द्र तिवारी

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। **R.N.I NO. UPHIN/2009/34814 मो0 नं0 -9511151254,** E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

योग दिवस से पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, 14 जून को आयुष मंत्रालय के ऑनलाइन योग सत्र में जुड़ेंगे लाखों लोग

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक अनूठी पहल होने जा रही है। आयुष मंत्रालय 14 जून को एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र आयोजित करेगा, जिसमें एक साथ सबसे अधिक लोगों की भागीदारी दर्ज कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका होगी। यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इसमें अधिक से अधिक सहभागिता करने के लिए कहा है

यूट्यूब पर होगा योग सत्र का सीधा प्रसारण

आयुष मंत्रालय और हैबिल्ड हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यह कार्यक्रम सुबह 6:15 बजे से 7:35 बजे तक आयोजित होगा। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। योग सत्र का सीधा प्रसारण आयुष मंत्रालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों को टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद वाट्सएप पर कार्यक्रम का लिंक भेजा जाएगा। रिकॉर्ड प्रयास के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को अपने मोबाइल, लैपटॉप या अन्य व्यक्तिगत डिवाइस से अलग-अलग लागिन करना होगा।गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हर पंजीकृत डिवाइस की उपस्थिति अलग से दर्ज की जाएगी। इसी वजह से संस्थानों से व्यक्तिगत भागीदारी को बढ़ावा देने को कहा गया है। यूजीसी के अनुसार यह पहल योग को जन-जन तक पहुंचाने, स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के संदेश को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

डीएम सर, आप मेरे स्कूल को बचा लीजिए; भविष्य की खातिर गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल पहुंची बच्चियां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त लखनऊ के स्कूल विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल, नरही का खाली कराने का विरोध काफी तेज होता जा रहा है। स्कूल खाली कराने के विवाद के बीच शनिवार को विद्यालय परिसर के बाहर विद्यार्थियों शिक्षकों, कर्मचारियों, अभिभावकों और प्रबंधन से जुड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंस्पायर अवार्ड विजेता कक्षा नौ की छात्रा तनीशा ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई, उसने कहा कि डीएम सर मेरे स्कूल को बचा लीजिए। हम सब गरीब हैं और इसी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने स्कूल पर कब्जा करने का प्रयास किया है। तनीशा ने कहा कि यह तो हमारे भविष्य का सवाल है। बच्चों के साथ ही शिक्षकों और अभिभावकों ने विद्यालय को कब्जे से मुक्त कराने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। विद्यालय की प्रबंधिका संतोष रस्तोगी के नेतृत्व में प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षिकाएं, कर्मचारी तथा अभिभावक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रशासनिक कार्रवाई के तहत पुलिस की मौजूदगी में विद्यालय परिसर को खाली कराया गया और विद्यालय के अभिलेख, फर्नीचर, पंखे, कंप्यूटर सहित अन्य शैक्षिक सामग्री बाहर निकाल दी गई। इससे विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण और विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी, महासचिव आशीष कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष नंद कुमार मिश्र, प्रचार मंत्री जेके यादव सहित शिक्षक संघ के अनेक पदाधिकारी भी प्रदर्शन का समर्थन किया। शर्मा गुट की ओर से महासचिव नरेन्द्र कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा और जिलामंत्री महेश चंद ने भी प्रदर्शन में भाग लिया। आशीष कुमार सिंह ने कहा कि विद्यालय और उससे जुड़े लोगों के हितों की काफी अनदेखी की गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराते तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। स्कूल प्रबंधन के समर्थन में आए मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि विद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था को जल्द बहाल किया जाए, जिससे छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो। 1936 में स्थापित इस विद्यालय को बंद करने की साजिश की जा रही है। 243 छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने दिया जाएगा।

बच्चों के भविष्य और गांव के माहौल को बचाने के लिए आगे आए कुढ़ा गांव के ग्रामीण, शराब ठेका हटाने की मांग

● .....संपूर्ण समाधान प्रभारी को सौंपा ज्ञापन, विद्यालय के माहौल और सामाजिक व्यवस्था पर पड़ रहे दुष्प्रभाव का उठाया मुद्दा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुढ़ा के ग्रामीणों ने बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और गांव के स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने के लिए सराहनीय पहल करते हुए स्कूल के निकट संचालित शराब की दुकान को हटाने की मांग उठाई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान प्रभारी (तहसील मोहनलालगंज) को सामूहिक हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र सौंपकर शराब के ठेके को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग की। ग्रामीणों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम सभा कुढ़ा के लिंक मार्ग पर बाजार के सामने संचालित शराब की दुकान से लगभग 150 मीटर की दूरी पर कक्षा 8 तक का पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्थित है। ग्रामीणों का कहना है कि शराब की दुकान के कारण विद्यालय के आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा है तथा बच्चों पर इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया कि कई बार कुछ लोग शराब पीने के बाद गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार करते हैं, जिससे विद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं, अभिभावकों और राहगीरों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि शराब पीने वाले कुछ लोग विद्यालय परिसर में लगे सरकारी नल का भी उपयोग करते हैं, जिससे विद्यालय परिसर की गरिमा प्रभावित होती है और बच्चों के साथ विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर पूर्व में भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल सका। इसी क्रम में शनिवार को सुरेंद्र कुमार सिंह, अजीत, मंजू, रामसेवक धीमान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान सहित सामूहिक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों के हित, शिक्षा के अनुकूल वातावरण और सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए शराब की दुकान को आबादी और विद्यालय क्षेत्र से दूर किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी मांग पर सकारात्मक विचार करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर एसयूवी डिवाइडर से टकराकर पलटी,चार घायल

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के उमरामऊ गांव के निकट गंगा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के चार लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित पटेल नगर निवासी एसके सक्सेना अपनी पत्नी प्रतिभा सक्सेना, साले विजय सक्सेना और उनकी पत्नी सुनीता सक्सेना के साथ प्रयागराज में गंगा स्नान कर घर लौट रहे थे। कार एसके सक्सेना चला रहे थे। उमरामऊ गांव के पास पहुंचते ही कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एसयूवी एक्सप्रेसवे पर ही पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों के मुताबिक सभी को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है। हादसे में एसयूवी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

पत्रकार रोहित मिश्रा का लंबी बीमारी के चलते निधन

● ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में लहरपुर पत्रकारों द्वारा दिवंगत पत्रकार रोहित मिश्रा के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रखा मौन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लहरपुर सीतापुर। जनपद के महोली क्षेत्र के रहने वाले एक निजी समाचार पत्र के मान्यता प्राप्त पत्रकार रोहित मिश्रा का लंबी बीमारी के चलते शनिवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर लगते ही पूरे पत्रकारिता समाज में शोक की लहर दौड़ गई। बताते चलें दिवंगत पत्रकार रोहित मिश्रा पिछले कई महीनो से कैंसर जैसी घातक बीमारी से जंग लड़ रहे थे जिसके चलते उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था शनिवार को वह बीमारी से लड़ने की जंग हार गए। जिसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में लहरपुर के पत्रकारों ने स्थानीय पक्के तालाब तीर्थ परिसर में एकत्र होकर दिवंगत पत्रकार रोहित मिश्रा के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। गौरतलब है कि इनके पिताजी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे व रोहित मिश्रा कांग्रेस के युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे। इस अवसर पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ पत्रकार कमलेश मेहरोत्रा, पंकज शुक्ला, अरुण सिंह आचार्य, गार्गी प्रसाद मिश्रा, अभिनव त्रिवेदी, आकाश सिंह, एहतिशाम बेग, देशप्रीत सिंह, अंकित अवस्थी,ओमकार वर्मा, हाशिम अंसारी, मौलाना सिराज, विपिन तिवारी, दिनेश शुक्ला, राज शुक्ला, वीरेश तिवारी, रामगोपाल दीक्षित, समीर अंसारी, अभिषेक मिश्रा सहित पत्रकार मौजूद रहे।

पारिवारिक विवाद सुलझाने गई पुलिस पर हमला

● चौकी इंचार्ज समेत पांच पुलिसकर्मी घायल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के लालबेग का पुरवा मजरे बहाई गांव में पारिवारिक विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना में चौकी इंचार्ज समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए।पुलिस ने पांच नामजद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बृहस्पतिवार रात एक महिला ने पारिवारिक विवाद की सूचना दी थी। सूचना पर पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर कांस्टेबल अमरदेव के साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने पर बहाई चौकी इंचार्ज एसआई अजय मिश्रा, सुमित विश्वकर्मा, निमंग रिछारिया और होमगार्ड देवतादीन मौके पर पहुंचे। आरोप है कि हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। घटना में पांचों पुलिसकर्मी घायल हो गए। कांस्टेबल अमरदेव की तहरीर पर दीपू, रंजीत, सुधांशु, देवी और खुशी समेत 10 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

दो बाइकों की भिड़ंत में भाई-बहन घायल,गंभीर हालत में युवक रेफर

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव के निकट शुक्रवार को देर शाम दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार भाई बहन घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। शोभवापुर गांव निवासी रामलखन अपनी बहन गुड़िया को बाइक से बाजार लेकर जा रहा था। सेमरपहा गांव के पास सामने से आ रही एक बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घटना के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से चला गया। आसपास के लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया।रामलखन की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बहन गुड़िया का उपचार सीएचसी में किया गया।

'ए ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन' विषय पर एक महत्वपूर्ण तकनीकी व्याख्यान का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), उत्तर प्रदेश स्टेट सेन्टर, लखनऊ द्वारा 'विश्व पर्यावरण दिवस' के अवसर पर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स भवन, आई.ई.आई., रिवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ में 'ए ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन' विषय पर एक महत्वपूर्ण तकनीकी व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. अवधेश कुमार सिंह, मानद प्रोफेसर, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश ने सहभागिता की। अपने व्याख्यान में उन्होंने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बढ़ते वैश्विक तापमान, प्रदूषण एवं पर्यावरणीय असंतुलन की चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग तथा पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं एवं अभियंताओं से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों एवं नवाचारों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरणीय चुनौतियों एवं उनके समाधान पर सार्थक चर्चा हुई। उपस्थित अभियंताओं, शिक्षाविदों एवं विद्यार्थियों ने विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका मुख्य वक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूतपूर्व अध्यक्ष (Past Chairman) प्रो० (डॉ.) भरत राज सिंह, आई.ई.आई. यू.पी. स्टेट सेंटर, लखनऊ द्वारा की गई। उन्होंने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता का स्वागत करते हुए उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योगदान का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, अभियंताओं, शिक्षाविदों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय चुनौतियाँ संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग तथा हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने अभियंताओं, शिक्षाविदों एवं युवाओं से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। अंत में उन्होंने उपस्थित सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन कार्यक्रम के संयोजक डॉ. ए.के. गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य वक्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योगदान का परिचय कराया तथा पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के क्षेत्र में उनके कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में संस्था के पूर्व मानद सचिव डॉ. जसवंत सिंह ने सभी अतिथियों, मुख्य वक्ता, अभियंताओं, शिक्षाविदों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

ऑनलाइन टिकट बेचकर सवारी ढोने वाली निजी पर्यटक बसों पर होगी कार्रवाई

● परिवहन विभाग 9 से 11 जून तक निजी पर्यटक बसों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाएगा, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सामान्य यात्री बसों की तरह टिकट बेच रही हैं।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये टिकट बेचकर सामान्य यात्री बसों की तरह संचालन कर रही निजी पर्यटक बसों पर अब परिवहन विभाग सख्ती करने जा रहा है। प्रदेशभर में नौ से 11 जून तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर बसों को सीज करने के साथ उनके परमिट निलंबित या निरस्त किए जा सकते हैं। परिवहन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) वाली कई निजी बसें रेडबस, मेक माईट्रिप, अभिबस, पेटीएम, इक्सिगो और ईज माई ट्रिप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीटवार टिकट बेच रही हैं।

ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साक्ष्य एकत्र कर मुख्यालय भेजने के निर्देश

ये बसें राष्ट्रीयकृत और अधिसूचित मार्गों पर सामान्य यात्री बसों की तरह यात्रियों को बैठा और उतार रही हैं, जबकि पर्यटक परमिट वाली बसों को इस तरह संचालन की अनुमति नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार का संचालन न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे निगम को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिन मार्गों पर रोडवेज बसें निर्धारित नियमों के तहत संचालित होती हैं, वहां निजी पर्यटक बसें ऑनलाइन टिकट बेचकर यात्रियों को आकर्षित कर रही हैं, जिससे रोडवेज की आय प्रभावित हो रही है। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने सभी उप परिवहन आयुक्तों, संभागीय परिवहन अधिकारियों, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों व यात्री व मालकर अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि वाहन अपने गृह राज्य से बाहर 60 दिन से अधिक न रहा हो, केवल अधिकृत पर्यटकों को ही यात्रा करा रहा हो और उसमें इमरजेंसी बटन लगे हों। यदि कोई एआईटीपी बस स्टेज कैरिज के रूप में संचालित मिलती है तो उसका परमिट निलंबित या निरस्त किया जाएगा और वाहन को सीज करने की कार्रवाई भी होगी। अधिकारियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साक्ष्य एकत्र कर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संबंधित संचालकों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके।

साहब! कोटेदार ने काट दिया हमारा राशन कार्ड, हम दिव्यांग

लालगंज (रायबरेली)। तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर चकसुखुलाल मजरे गौरा रुपई गांव निवासिनी एक महिला ने कोटेदार पर राशन कार्ड काटने का आरोप लगाया है। महिला ने प्रार्थना पत्र देकर राशन कार्ड बनवाने की गुहार लगाई है। महिला ने अपने दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह अनुसूचित जाति की दिव्यांग महिला है गांव के कोटेदार ने उसका राशन कार्ड काट दिया। महिला ने बताया कि कोटेदार ने अपने ही घर के कई लोगों के कार्ड बना रखे हैं। महिला ने बताया कि गांव के अन्य लोगों के राशन कार्ड भी काट दिए गए हैं इससे उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। वे किसान सम्मान निधि और पेंशन भी पाते हैं।अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सरेनी के दूधवन की रहने वाली साधना सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर पति की मौत के बाद मिलने वाले कृषक दुर्घटना बीमा को लेकर गुहार लगाई बताया कि कई बार प्रार्थना पत्र दिया लेकिन अभी तक उसे इस योजना का लाभ नहीं मिला है। इस प्रकार एसडीएम राजू श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कुल 35 शिकायत दर्ज की गई इनमें से आठ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया बाकी शिकायतों को संबंधित विभाग के अफसर को सौंपते हुए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए।

उम्मीद पोर्टल पर सुन्नी वक्फ की 30 हजार से ज्यादा संपत्तियां रद

● कागजों में गड़बड़ी के चलते हुई कार्रवाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। वक्फ संपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि बीतने पर उम्मीद पोर्टल ने सुन्नी वक्फ की 30,322 संपत्तियां और शिया वक्फ की 2060 संपत्तियों का पंजीयन रद किया है। उत्तर प्रदेश का पोर्टल बंद हो गया। राज्य में जिनकी संपत्तियां रद हुई हैं, उनके मुतवल्ली (रख रखाव करने वाला) के पास अब उच्च न्यायालय से संपत्ति अपलोड करने के लिये समय मांगने अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अदालती राहत नहीं मिलने पर प्रशासन राजस्व नियमों के तहत कदम उठा सकता है। केन्द्र सरकार ने 5 जून 2025 को वक्फ संपत्तियों का ब्योरा उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने का आदेश दिया था। छह माह का समय दिया गया। जिसके व्यतीत होने पर सुन्नी और शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायालय में समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका दायर की। अदालत ने 5 जून 2026 तक यानी छह माह का समय दिया। वक्फ अदालत को इससे अधिक समय देने का अधिकार नहीं है। 5 जून, रात 12 बजे यह समय सीमा बीतने तक सुन्नी वक्फ की 103,542 संपत्तियों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड किया गया। जिसमें से 30,322 संपत्तियों को दस्तावेजों की त्रुटियों के चलते रद कर दिया।

अदालत के आदेश से ही अब पोर्टल होगा अनलॉक

कई दस्तावेजों का वक्फ बोर्डों के कागजों से मेल नहीं था। वह कहते हैं कि जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी के चलते खसरा खतौनी के नम्बरों का बदलाव हो गया, मगर वक्फ बोर्डों ने अपने दस्तावेजों को ठीक नहीं कराया। जिसका खामियाजा मुतवल्लियों को उठाना पड़ेगा। वह बताते हैं कि मुतवल्लियों के सामने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अदालत के आदेश से ही अब पोर्टल को अनलॉक (खोला) जा सकेगा। वह कहते हैं कि आगे की कानूनी लड़ाई कठिन होगी।

सीतापुर के सिधौली में बनेगा मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल विद्यालय

● शासन ने दी 25 करोड़ रुपये की मंजूरी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। सिधौली के गुलरिया में मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल विद्यालय के लिए शासन ने 25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह आधुनिक विद्यालय 12 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इस आधुनिक विद्यालय में एक ही छत के नीचे कक्षा एक से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की सुविधा होगी। यह विद्यालय पूरी तरह आवासीय होगा। पिछले वर्ष एक सीएम कंपोजिट विद्यालय को परसेंडी के खजुरिया माफी में मंजूरी मिली थी, जिसका निर्माण तेजी से चल रहा है। सिधौली में स्वीकृत किया गया यह जिले का दूसरा विद्यालय होगा। मुख्यमंत्री माडल विद्यालय के लिए शासन ने 24.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा। कार्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को मिली है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय में स्मार्ट क्लास, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं होंगी। डिजिटल प्लेटफार्म व लर्निंग युक्त संसाधनों की व्यवस्था रहेगी। विद्यालय में 42 आधुनिक क्लास रूम के साथ 1500 बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी। इन विद्यालयों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। यहां स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर और लैंग्वेज लैब के अलावा रोबोटिक्स व मशीन लर्निंग भी छात्रों को पढ़ाई जाएगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से पढ़ाई होगी। एक बड़ा बहुउद्देशीय हाल भी बनाया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। इसके साथ स्किल हेल्प सेंटर बच्चों के कौशल विकास में मददगार बनेगा। इन विद्यालयों में स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा होगी। विद्यालय परिसर सीसीटीवी कैमरे व सोलर पैनल से युक्त होगा। प्रदेश सरकार की इस परियोजना में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वित्तीय सहयोग कर रहा है।

अस्पताल में घुसकर पति ने किया हमला,लहूलुहान

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाली महिला ने अपने पति पर ब्लेड से हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।महिला मोनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह एक निजी नर्सिंग होम संचालक के घर पर काम करती है। पति से उसका लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी वजह से वह अपने सात वर्षीय बेटे के साथ अलग रहकर किसी तरह गुजर बसर कर रही है। आरोप है कि शुक्रवार शाम उसका पति अस्पताल पहुंच गया। वहां उसे अकेला पाकर गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की। महिला का कहना है कि आरोपी ने ब्लेड से कई वार किए। इससे उसके कान, गले और हाथ में चोटें आईं। घटना के बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में चूक

● रास्ता भटककर टेढ़ी पुलिया पहुंचा वाहनों का काफिला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा में शुक्रवार को बड़ी चूक देखने को मिली। राजनाथ सिंह के वाहनों का काफिला उनके संसदीय क्षेत्र लखनऊ में ही भटक गया। राजनाथ सिंह शुक्रवार को जगद्गुरु रामभद्राचार्य की श्रीराम कथा से लौट रहे थे, इसी दौरान उनके वाहनों का काफिला रास्ता भटककर टेढ़ी पुलिया पहुंच गया। श्रीराम कथा से लौटते समय लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर इनके पायलट मार्ग चूक गए और फ्लाईओवर की जगह नीचे का रास्ता पकड़ लिया और सीधे टेढ़ी पुलिया चौराहा पहुंच गए। टेढ़ी पुलिया चौराहा पर अचानक वीवीआईपी वाहनों का काफिला पहुंचने से पुलिस की टीम में खलबली मच गई। यहां पर पहले से बंद रास्ते की बैरिकेडिंग हटाकर जल्दी से काफिले को वापस मुख्य मार्ग पर मोड़ा गया। इस दौरान कुछ मिनटों तक यातायात ठप रहा, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत स्थिति संभाल ली। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला शुक्रवार शाम एक मार्गीय चूक के कारण निर्धारित रास्ते से भटक गया। सीतापुर रोड पर ब्रज की रसोई परिसर में आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम से लौटते समय उनके वाहनों का काफिला इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से ओवरब्रिज के ऊपर जाने के बजाय नीचे के मार्ग से होते हुए टेढ़ी पुलिया चौराहे तक पहुंच गया। निर्धारित रूट के अनुसार काफिले को मड़ियांव ओवरब्रिज से उतरकर इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पार करते हुए फ्लाईओवर पर चढ़ना था। उधर रक्षा मंत्री के आवागमन को देखते हुए इंदिरा नगर के मुंशी पुलिया की ओर जाने वाले वाहनों को पहले से ही रोक दिया गया था। ऐसे में वीवीआईपी काफिले के अचानक टेढ़ी पुलिया पहुंचने की सूचना मिलते ही अधिकारियों में खलबली मच गई। उनकी सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने तत्काल स्थिति संभाली और चौराहे पर लगी बैरिकेडिंग हटाकर काफिले को वापस इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे की ओर मोड़ा। इसके बाद काफिला निर्धारित मार्ग पर लाया गया और फ्लाईओवर के रास्ते आगे रवाना किया गया।

संक्षिप्त खबरें

हर्ष फायरिंग में महिला की मौत में बिहार के भाजपा विधायक राजू सिंह दोषी करार, 9 जून को होगी सजा पर सुनवाई

दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2018 में नव-वर्ष समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला की मौत के मामले में बिहार के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 (गैर-इरादतन हत्या) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार देते हुए उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। मामले में सजा की अवधि पर नौ जून को सुनवाई होगी। अदालत ने राजू सिंह की पत्नी, रमेंद्र सिंह और राणा राजेश सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। घटना के अनुसार, 31 दिसंबर 2018 की रात नई दिल्ली के मंडी गांव स्थित रोज फार्म में आयोजित नववर्ष पार्टी के दौरान विकास गुप्ता अपनी पत्नी अर्चना गुप्ता और बेटी के साथ मौजूद थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, रात करीब 12 बजे उन्होंने राजू सिंह और उनके चालक हरि सिंह को हथियारों से हवाई फायरिंग करते देखा। कुछ मिनट बाद फिर फायरिंग हुई, जिसके बाद अर्चना गुप्ता अचानक जमीन पर गिर गईं। उनके चेहरे पर खून था और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस जांच में यह सामने आया कि पार्टी के दौरान चली गोली से अर्चना घायल हुई थीं और घटनास्थल पर पड़ा खून भी साफ कर दिया गया था। एक जनवरी 2019 को फतेहपुर बेरी थाने में पहले हत्या के प्रयास, साक्ष्य मिटाने और आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान घटनास्थल से .22 बोर के दो इस्तेमाल किए गए कारतूस बरामद हुए। राजू सिंह के घर से भी हथियार और कारतूस बरामद किए गए, जबकि उनके चालक हरि सिंह के घर से एक .315 बोर राइफल और अन्य सामग्री मिली थी। जांच में यह भी सामने आया कि फायरिंग के बाद राजू सिंह और उनका चालक मौके से फरार हो गए थे। दोनों को दो जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के फाजिलनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय राजू सिंह के पास से .22 बोर की पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। उपचार के दौरान तीन जनवरी 2019 को अर्चना गुप्ता की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा हटाकर हत्या का मामला दर्ज किया। एम्स में हुए पोस्टमार्टम में डाक्टरों ने स्पष्ट किया कि अर्चना की मौत सिर में गोली लगने से हुई चोट के कारण हुई थी। उल्लेखनीय है कि 30 अक्टूबर 2023 को अदालत ने राजू सिंह की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ धारा 304 (भाग-2) और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए थे।

कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर की बढ़ीं मुश्किलें, 8 जून को दाखिल करेंगे अग्रिम जमानत याचिका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान (खान सर) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पटना के कदमकुआं क्षेत्र स्थित कोचिंग संस्थान से जुड़े फायरिंग मामले में दर्ज एफआईआर के बाद कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। ताजा घटनाक्रम में खान सर ने फिलहाल अदालत में आत्मसमर्पण नहीं करने का फैसला लिया है और 8 जून को अग्रिम जमानत (एंटिसिपेटरी बेल) के लिए याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि उनके मुवक्किल फिलहाल पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की जाएगी। अदालत के निर्णय के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग संस्थान के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे। घटना के बाद बड़ी संख्या में छात्र संस्थान के बाहर एकत्र हो गए थे और पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा था। इस प्रकरण में पुलिस ने खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं, खान सर के समर्थकों का कहना है कि उन्हें साजिश के तहत विवाद में घसीटा जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मामले ने शिक्षा जगत और छात्र समुदाय में व्यापक चर्चा पैदा कर दी है। अब सबकी निगाहें 8 जून को दाखिल होने वाली अग्रिम जमानत याचिका और अदालत के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत के आदेश के बाद मामले की दिशा काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी।

पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में अल्का लांबा दोषी करार

दिल्ली। महिला आरक्षण की मांग को लेकर वर्ष 2024 में हुए संसद घेराव प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी करार दी गई कांग्रेस नेता अलका लांबा को अदालत ने शनिवार को परिवीक्षा (प्रोबेशन) का लाभ देते हुए एक वर्ष के लिए अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने अलका लांबा को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। मामले में अदालत ने 25 मई को अलका लांबा को दोषी करार दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि उन्होंने निषेधाज्ञा के आदेशों की अनदेखी की और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान लांबा की ओर से अच्छे आचरण के आधार पर प्रोबेशन पर रिहा किए जाने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने उन्हें लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने, लागू आदेश की अवहेलना करने और सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के आरोपों में दोषी ठहराया था।

तिहाड़ जेल में डर रहे संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, कोर्ट में लगाई गुहार- हमारे ऊपर हो सकता है हमला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने संसद सुरक्षा चूक मामले में तीन आरोपितों ने जेल के अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। आरोपितों ने दावा किया कि उन्हें अन्य विचाराधीन कैदियों से हमले का खतरा है और उन्हें दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने उनकी अर्जी पर संबंधित जेल प्रशासन को कानून के मुताबिक उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने मामले से जुड़े चार आरोपितों की न्यायिक हिरासत भी आठ जुलाई तक बढ़ा दी। मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। सुनवाई के दौरान आरोपित मनोरंजन डी, ललित झा और सागर शर्मा ने अदालत को बताया कि उन्हें जेल में सुरक्षा संबंधी खतरा महसूस हो रहा है। मनोरंजन डी और ललित झा फिलहाल जेल नंबर-आठ में बंद हैं, जबकि सागर शर्मा जेल नंबर-एक में है। तीनों ने अदालत से उन्हें जेल नंबर-चार में स्थानांतरित करने की मांग की। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि जेल में स्थानांतरण का विषय जेल प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद अदालत ने संबंधित जेल अधिकारियों को आरोपितों की याचिकाओं पर नियमों के अनुसार फैसला लेने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान सभी आरोपित अदालत में पेश हुए। यह मामला 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक से जुड़ा है। उस दिन दो आरोपित विजिटर गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और पीले रंग का धुआं छोड़ने वाले कैनिस्टर का इस्तेमाल किया था। इसी दौरान संसद भवन के बाहर भी दो अन्य लोगों ने नारेबाजी करते हुए पीला धुआं छोड़ा था।

लंबे समय से लंबित मांग, दुल्लभछड़ा-बदरपुर ट्रेन को सिलचर तक विस्तारित करने की जोरदार अपील

● पुरानी मीटर गेज समय-सारिणी बहाल करने की मांग, शाम की ट्रेन सिलचर तक चलाने हेतु रेल मंत्री से हस्तक्षेप की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि- जिले के दुल्लभछड़ा-बदरपुर रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेन को सिलचर तक विस्तारित करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराज़गी और निराशा बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, मीटर गेज समय में यह ट्रेन दोपहर लगभग 2:30 बजे दुल्लभछड़ा से चलकर रात लगभग 7:30 से 8:00 बजे के बीच सिलचर पहुंचती थी। इससे कर्मचारी, व्यापारी, छात्र-छात्राएं और आम यात्रियों को काफी सुविधा मिलती थी। वर्तमान में 55689 नंबर की ब्रॉड गेज ट्रेन केवल दुल्लभछड़ा से बदरपुर तक ही सीमित है, जिससे सिलचर जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि पुरानी समय-सारिणी के अनुसार शाम की ट्रेन को दुल्लभछड़ा से चलाकर सिलचर तक विस्तारित किया जाए, तो यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही बराक घाटी की परिवहन व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। स्थानीय नागरिकों और बुद्धिजीवियों ने रेलवे मंत्रालय से आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाए और जनहित में आवश्यक कदम उठाए जाएं। उनका मानना है कि मीटर गेज समय-सारिणी के आधार पर यदि नई योजना बनाई जाती है, तो दुल्लभछड़ा, बदरपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सिलचर से बेहतर और सुगम संपर्क मिल सकेगा। लोगों ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी इस विषय में हस्तक्षेप करने की अपील की है, ताकि रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शीघ्र उचित निर्णय ले सके।

जिले के बदरपुर एन.सी. कॉलेज ऑडिटोरियम परिसर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जागरूकता सभा व हस्ताक्षर अभियान

● 300 से अधिक लोगों ने किए हस्ताक्षर, न्याय के लिए आंदोलन को और मजबूत करने का आह्वान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि- असम के बराक घाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को मजबूत करने के उद्देश्य से हाईकोर्ट बेंच मांग कार्यान्वयन समिति, कछार जिला समिति के तत्वावधान में 6 जून शनिवार को बदरपुर एन.सी. कॉलेज ऑडिटोरियम परिसर में जागरूकता सभा एवं जन हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, राजनीतिक प्रतिनिधियों, समाजसेवियों, छात्र-छात्राओं तथा विभिन्न वर्गों के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 2 बजे जागरूकता सभा से हुआ। सभा में समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुमार साहा, कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रो. अरुण कुमार सेन, प्राचार्य पार्थ सारथी दास, सामयिक प्रसंग पत्रिका के संपादक तैमूर राजा चौधरी, अधिवक्ता सुमिता पोद्दार, विश्व बरुण बरुआ, धर्मानंद देव, भाजपा नेता दीपक देव, प्रो. जयनाल आबेदीन तापादार, अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती एवं तुहिना शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कटीगड़ा के विधायक कमलाक्ष्य पुरकायस्थ कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने लिखित संदेश भेजकर हाईकोर्ट बेंच की मांग का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। उनका संदेश सभा में पढ़ा गया। उन्होंने कहा कि यह मांग बराक घाटी के लाखों लोगों की न्यायसंगत और जनहित से जुड़ी पुरानी मांग है तथा न्यायिक सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए स्थायी बेंच की स्थापना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यायिक कार्यों के लिए लोगों को गुवाहाटी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय, धन और श्रम की हानि होती है। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थायी बेंच स्थापित होने से न्याय प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और किफायती होगी। स्वागत भाषण में प्रो. अरुण कुमार सेन ने कहा कि न्याय प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और यह मांग पूर्णतः न्यायसंगत है। समिति अध्यक्ष ध्रुव कुमार साहा ने कहा कि लगभग 40 लाख आबादी वाले बराक घाटी क्षेत्र के लिए

हाईकोर्ट बेंच आज समय की आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि न्यायिक मामलों के लिए लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण अधिवक्ता धर्मानंद देव की तथ्यपरक पावर प्वाइंट प्रस्तुति रही। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों और न्यायिक व्यवस्था के विकासक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि फोर्ट विलियम कोर्ट से लेकर शिलांग और गुवाहाटी हाईकोर्ट तक की न्यायिक यात्रा के बीच बराक घाटी में स्थायी बेंच की आवश्यकता स्पष्ट रूप से बनती है। सभा में उपस्थित वक्ताओं ने इस मांग को जनहित से जुड़ा बताते हुए सरकार से शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि न्याय तक समान पहुंच का जनआंदोलन है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मौनिता नाथ ने किया तथा प्रश्नोत्तर सत्र का संचालन अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती ने किया। अंत में प्रो. जयनाल आबेदीन तापादार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसके बाद शाम 5 बजे जन हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ, जिसमें महिला-पुरुष, छात्र-छात्राएं, शिक्षक, व्यापारी एवं विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों के अनुसार इस अभियान में 300 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर समर्थन व्यक्त किया। समिति ने बताया कि भविष्य में भी इस मांग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसी क्रम में आगामी 8 जून को सोनाई एम.सी. कॉलेज परिसर में भी जागरूकता सभा एवं हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने लोगों से अपील की कि वे इस जनआंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाएं और न्यायसंगत मांग को मजबूत करें। समिति ने विश्वास व्यक्त किया कि जनसमर्थन के बल पर यह लंबित मांग एक दिन अवश्य पूरी होगी।

जर्मनी की राजनीति में बड़ा झटका: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट गंवाने पर बढ़ी सरकार की मुश्किलें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बर्लिन। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले जर्मनी को इस सप्ताह एक बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) की अस्थायी सदस्यता के चुनाव में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, जिससे देश की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में जर्मनी आवश्यक समर्थन जुटाने में असफल रहा। पश्चिमी यूरोपीय समूह की सीटों के लिए हुए चुनाव में ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल को सफलता मिली, जबकि जर्मनी पहली बार इस तरह की महत्वपूर्ण हार का सामना कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के वर्षों में जर्मनी की विदेश नीति, विशेषकर यूक्रेन युद्ध, इज़राइल समर्थन और विदेशी सहायता बजट में कटौती जैसे मुद्दों ने कई देशों को उससे दूर कर दिया। यही कारण रहा कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों का अपेक्षित समर्थन जर्मनी को नहीं मिल सका। जर्मनी के विदेश मंत्री और सरकारी अधिकारियों ने इस परिणाम पर निराशा व्यक्त की है। सरकार का कहना है कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखेगी और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में योगदान देती रहेगी। हालांकि विपक्षी दलों ने इसे सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया है और विदेश नीति की समीक्षा की मांग की है। इस हार के बाद जर्मनी में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप और वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों के बीच संतुलन बनाने में जर्मनी अपेक्षित सफलता

हासिल नहीं कर पाया। इसके चलते उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को झटका लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना केवल एक चुनावी हार नहीं बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का संकेत भी है। आने वाले समय में जर्मनी को अपनी विदेश नीति, विकास सहयोग कार्यक्रमों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को और मजबूत करना होगा ताकि वह विश्व मंच पर अपनी प्रभावशाली भूमिका बनाए रख सके।

Pre-SIR के तहत वोटर मैपिंग के लिए जिले के सभी 400 पोलिंग बूथ पर स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे

● वोटर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने बूथ पर पहुंचकर मैपिंग करवा सकेंगे- विराज एस. तिड़के

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बताए गए 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स को मंजूरी दी गई है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मालेरकोटला- चीफ इलेक्शन ऑफिसर, पंजाब, चंडीगढ़ के निर्देशानुसार, मालेरकोटला जिले के असेंबली हलके-105 मालेरकोटला और असेंबली हलके-106 अमरगढ़ के सभी 400 पोलिंग बूथ पर कल, 07 जून, 2026 (रविवार) को मौजूदा वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड वोटरों को साल 2003 की वोटर लिस्ट से मैप करने के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे।यह जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर-कम-डिप्टी कमिश्नर विराज एस. तिड़के ने बताया कि कैंप के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs)

उपायुक्त ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले 11 प्रकार के दस्तावेजों को मंजूरी दी है। इनमें सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी/ एससी/ एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी रिकॉर्ड, परिवार रजिस्टर और सरकार द्वारा जारी भूमि या घर आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि आधार कार्ड के संबंध में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने बूथों पर पहुंचने और मैपिंग प्रक्रिया को सफल बनाने की अपील की।

चोरी के मामले में दो अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का मोबाइल और नकदी बरामद

प्रयागराज। जार्जटाउन पुलिस ने चोरी के एक मामले में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किया गया मोबाइल फोन एवं नकद रुपये बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। पुलिस के अनुसार थाना जार्जटाउन में पंजीकृत मु0अ0सं0-95/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित मामले की विवेचना के दौरान पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर थाना जार्जटाउन पुलिस ने के.पी. बस स्टैंड के पास से दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अजीत पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम सरपतीपुर, थाना सरायइनायत, जनपद प्रयागराज तथा सूरज यादव पुत्र अतर सिंह यादव निवासी जुनैदपुर, थाना सरायइनायत, जनपद प्रयागराज के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की घटना से संबंधित सामान बरामद किया गया।

डाक अधीक्षक द्वारा किया गया वृक्षारोपण

सीतापुर- डाक घर के प्रांगण में डाक अधीक्षक राजेश कुमार तिवारी जी के करकमलों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया तथा सभी को अधिकाधिक वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित किया गया।

25 दिनों से अंधेरे में उपभोक्ता: 25 केवीए ट्रांसफार्मर पर 40-45 कनेक्शन

● बिल पूरा लेकिन बिजली शून्य; मुख्यमंत्री जी, इसका जिम्मेदार कौन?

बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही या सिस्टम की नाकामी?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोण्डा। जनपद गोण्डा के विकासखंड रुपईडीह अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र खरगूपुर के क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम माथेडीह से लेकर भवानीपुर उपाध्याय चौराहे तक, आर्यनगर-महराजगंज मार्ग के किनारे रहने वाले विद्युत उपभोक्ता पिछले लगभग 25 दिनों से भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भीषण गर्मी और उमस के बीच दर्जनों परिवारों के घरों में अंधेरा पसरा हुआ है, जबकि अधिकांश उपभोक्ताओं का विद्युत बिल भी बकाया नहीं है।ग्रामीणों का आरोप है कि यह समस्या किसी एक दिन की तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि विभागीय उदासीनता और वर्षों से चली आ रही अनदेखी का परिणाम है। लोगों का कहना है कि गांव में स्थापित 25 केवीए ट्रांसफार्मर पर लगभग 40 से 45 कनेक्शन संचालित किए जा रहे हैं, जिसके कारण लगातार ओवरलोड की स्थिति बनी रहती है। सवाल यह है कि जब ट्रांसफार्मर की क्षमता सीमित थी, तो उस पर इतने अधिक कनेक्शन स्वीकृत क्यों किए गए?प्रभावित उपभोक्ताओं में रामकुमार पुत्र जयराम (कनेक्शन संख्या 9575540100), रामप्रसाद पुत्र जयराम, भगवान चरण, लाला, घनश्याम, छोटे मौर्य सहित एक दर्जन से अधिक परिवार शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे हर महीने समय से बिजली बिल जमा करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें न तो पर्याप्त बिजली मिल रही है और न ही उनकी शिकायतों का समाधान।

बिल पूरा, बिजली गायब — आखिर क्यों?

ग्रामीणों का कहना है कि जब पिछले 25 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है, तो आखिर उनसे किस बात का बिल लिया जाएगा? यदि बिजली का उपयोग ही नहीं हुआ, तो उपभोक्ताओं पर बिल का बोझ डालना कैसे उचित माना जा सकता है?लोगों का आरोप है कि विभाग बिल वसूली में तो पूरी तत्परता दिखाता है, लेकिन जब उपभोक्ताओं को सुविधा देने की बात आती है, तो जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।

कई शिकायतें, फिर भी नहीं हुआ समाधान

ग्रामीणों के अनुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने और बिजली आपूर्ति सुचारू कराने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिणामस्वरूप बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, पेयजल संकट गहरा रहा है और बुजुर्गों व महिलाओं को भीषण गर्मी में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री जी, इसका जिम्मेदार कौन?

प्रदेश सरकार गांव-गांव तक बेहतर बिजली व्यवस्था पहुंचाने का दावा कर रहे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की बात करते हैं। ऐसे में गोण्डा जनपद के रुपईडीह विकासखंड अंतर्गत माथेडीह से भवानीपुर उपाध्याय चौराहे तक के उपभोक्ता पूछ रहे हैं–

मुख्यमंत्री जी, जब उपभोक्ता नियमित रूप से बिल जमा कर रहे हैं, तो 25 दिनों से बिजली से वंचित रहने का जिम्मेदार कौन है?

मुख्यमंत्री जी, 25 केवीए ट्रांसफार्मर पर 40-45 कनेक्शन देने की अनुमति किसने दी?

मुख्यमंत्री जी, शिकायतों के बाद भी यदि समाधान नहीं हो रहा, तो जवाबदेही किसकी तय होगी?

आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई और ट्रांसफार्मर की क्षमता नहीं बढ़ाई गई, तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और

उच्चाधिकारियों का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे।इस संबंध में एसडीओ पंकज राठौर ने बताया कि शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं जेई खरगूपुर रवि वर्मा ने कहा कि समस्या की जानकारी है और जल्द समाधान का प्रयास किया जाएगा।

जनता के सवाल

25 केवीए ट्रांसफार्मर पर 40-45 कनेक्शन क्यों दिए गए?

25 दिनों से बाधित बिजली आपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी है?

जब बिजली नहीं मिली तो बिल क्यों लिया जाए?

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

क्या विभागीय लापरवाही की जांच होगी?

माथेडीह और भवानीपुर उपाध्याय चौराहे के बीच रहने वाले उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि बिजली और जवाबदेही चाहिए। अब देखना यह है कि विभाग इन सवालों का जवाब देता है या फिर जनता को अपनी आवाज सड़क पर बुलंद करनी पड़ेगी।

ओटीटी पर छा गई करिश्मा कपूर की 7 एपिसोड वाली सीरीज 'ब्राउन'

● करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर राज कर रही है। इस सीरीज को IMDb से धांसू रेटिंग मिली है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दो साल बाद करिश्मा कपूर ओटीटी की दुनिया में लौटीं लेकिन वेब सीरीज लेकर। इस बार मेन लीड में करिश्मा थीं और नई कहानी के साथ ओटीटी पर धमाल मचा दिया। 24 घंटे के अंदर ही करिश्मा की सीरीज ओटीटी पर छा गई है। करिश्मा कपूर की नई वेब सीरीज ब्राउन है। रोमांटिक और ग्लैमरस रोल्स में नजर आने वालीं करिश्मा ने अपने करियर में पहली बार क्राइम थ्रिलर में ब्राउन जैसा किरदार निभाया हो। इस सीरीज में एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की जा रही है।

क्या है ब्राउन सीरीज की कहानी?

7 एपिसोड की सीरीज ब्राउन में करिश्मा कपूर पुलिस ऑफिसर की

भूमिका निभा रही हैं। सीरीज की कहानी रीटा ब्राउन (करिश्मा कपूर) की है जो शराब की लत से जूझ रही एक बदनाम डिटेक्टिव हैं और महिलाओं को निशाना बनाने वाले एक सीरियल किलर की जांच कर रही हैं। अभीक बरुआ के नॉवेल 'सिटी ऑफ डेथ' पर आधारित यह सात एपिसोड की नॉयर सीरीज मर्डर मिस्ट्री के साथ-साथ मुख्य किरदार के दुख, ट्रॉमा और खुद को सुधारने की यात्रा को भी दिखाती है।

किस ओटीटी पर है ब्राउन?

अभिनय देव के निर्देशन में बनी वेब सीरीज ब्राउन में करिश्मा कपूर के अलावा जिशु सेनगुप्ता, अर्जुन सिन्हा, सोनी राजदान जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म में सलमान खान की सौतेली मां और एक्ट्रेस हेलेन भी हैं। यह सीरीज 5 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है। यह आते ही ट्रेंडिंग लिस्ट में छा गई है।

सीरीज को मिली धांसू रेटिंग

करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन साल की सबसे टॉप रेटेड साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर बन गई है। इस सीरीज को IMDb की तरफ से 9.3 रेटिंग मिली है। इसका ऐलान करते हुए जी5 ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'डार्क। जबरदस्त। बेमिसाल। ब्राउन ने फैन्स और क्रिटिक्स को दीवाना बना दिया है और इसकी रेटिंग्स खुद ही सब कुछ बयां कर रही हैं।'